3 मोदी के नेतृत्व में भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

5 राजनीति, क्रिकेट और पत्रकारिता की त्रिवेणी

6 बेलगाम अमेरिका के सामने संयुक्त राष्ट्र लाचार

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 36 प्रति सोमवार, 12 जनवरी 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

स्वच्छ शहर में दूषित व्यवस्था ने खोली प्रशासनिक कमजोरियाँ

क्या इंदौर दूषित जल हादसे के असली जिम्मेदार सीएम और उनके खास इंदौर के प्रशासनिक अधिकारी है?

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

नई सरकार बनने के बाद दो साल हो गये हैं। पर इन दो सालों में प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को खोखला करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। जिसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि कैसे बीजेपी के मालवा के सबसे कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को कैसे कमजोर किया जाए। हर प्रशासनिक अधिकारी की जमावट मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं की गई, इससे आगे जाकर वो खुद ही इंदौर के प्रभारी मंत्री बन गए। पिछले 02 साल में इंदौर को कमजोर किया गया, जिसके फलस्वरूप इंदौर में क्राइम, ड्रग्स और भ्रष्टाचार बढ़ता ही गया। इंदौर को उज्जैन से चलाने का नतीजा है भागीरथपुरा दूषित पानी कांड। इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और उनके अपने इंदौर के अधिकारियों की है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल के कारण कई

परिवारों का उजड़ जाना केवल एक स्थानीय दुर्घटना नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिंह है। देश के स्वच्छतम शहर के तमगे के बीच यदि नागरिक गंदा पानी पीने को मजबूर हों और उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़े तो यह घटना नहीं व्यवस्था की विफलता कही जाएगी। इस त्रासदी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है और ऐसे हादसों को रोकने के लिए नेतृत्व स्तर पर कौनसा दृष्टिकोण जरूरी था? यह निर्विवाद है कि पेयजल आपूर्ति जैसी मूलभूत सेवा में चूक का सीधा असर आमजन के जीवन पर पड़ता है। भागीरथपुरा में जो हुआ, उसने नगर निगम, जिला प्रशासन और राज्य सरकार तीनों की जवाबदेही को कठघरे में खड़ा कर दिया। आरोप यह है कि चेतावनियों के बावजूद समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, निगरानी ढीली रही और समन्वय की कमी ने संकट को गहराया। ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिक नेतृत्व की संवेदनशीलता और प्रशासनिक अनुभव निर्णायक भूमिका निभाते हैं। (शेष पेज 2 पर)

जनजातीय संस्कृति के संरक्षण में छत्तीसगढ़ की सशक्त पहल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का दूरदर्शी मॉडल सफलता की ओर अग्रसर

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध जनजातीय परंपराओं, लोक संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के लिए देश भर में विशिष्ट पहचान रखता है। राज्य की आत्मा उसकी जनजातीय संस्कृति में बसती है, जहाँ आस्था, प्रकृति और सामुदायिक जीवन एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और अनुष्ठानों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में ऐसे ठोस और दूरदर्शी कदम उठाए हैं, जो न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करने का आधार बन रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट दृष्टि के साथ यह समझा है कि जनजातीय समाज का विकास केवल आर्थिक योजनाओं से संभव नहीं है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान, श्रद्धा स्थलों और परंपराओं को सम्मान और संरक्षण देना भी उतना ही आवश्यक है।

इसी सोच के तहत राज्य सरकार द्वारा अखरा विकास योजना को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। (शेष पेज 3 पर)

सत्ता, सिंडिकेट और भूपेश बघेल की राजनीतिक जवाबदेही पर उठते सवाल

-विजया पाठक

बघेल शासनकाल के खुलते कथित शराब घोटाले की परतें

छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले ने राज्य की राजनीति को केवल हिलाया ही नहीं है, बल्कि सत्ता, प्रशासन और परिवारवाद के आपसी संबंधों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राज्य की एंटी-करप्शन ब्यूरो/आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा द्वारा दाखिल की गई चार्जशीटों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जिस तरह से केंद्रीय भूमिका में रखा गया है, उसने इस मामले को सामान्य भ्रष्टाचार प्रकरण से कहीं आगे पहुंचा दिया है। यह मामला केवल वित्तीय अनियमितताओं तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि यह कथित तौर पर सत्ता के संरक्षण में विकसित एक संगठित सिंडिकेट, प्रशासनिक मिलीभगत और राजनीतिक प्रभाव के इस्तेमाल की कहानी प्रस्तुत करता है।

सत्ता के दौरान बना कथित "शराब सिंडिकेट"

ईडी और एसीबी, ईओडब्ल्यू के अनुसार, 2019 से 2022 के बीच—जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी-राज्य में शराब के कारोबार को नियंत्रित करने के नाम पर एक ऐसा तंत्र विकसित हुआ, जिसने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया और निजी लाभार्थियों को भारी फायदा दिलाया। (शेष पेज 2 पर)

क्या इंदौर दूषित जल हादसे के असली जिम्मेदार सीएम और उनके खास इंदौर के प्रशासनिक अधिकारी है?

(पेज 1 का शेष)

त्वरित निर्णय और प्रशासन पर मजबूत पकड़ की कमी

यहीं पर कैलाश विजयवर्गीय का संदर्भ स्वतः उभरता है। इंदौर जैसे बड़े, घनी आबादी वाले और जटिल शहरी ढांचे वाले शहर को संभालने के लिए केवल आदेशात्मक शैली नहीं, बल्कि जमीनी समझ, त्वरित निर्णय और प्रशासन पर मजबूत पकड़ की जरूरत होती है। कैलाश विजयवर्गीय का लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव, शहरी निकायों की कार्यप्रणाली पर उनकी पकड़ और संकट के समय हस्तक्षेप की उनकी शैली इंदौर ने पहले भी देखी है। उनके रहते नगर निगम और जिला प्रशासन के बीच समन्वय अधिक सशक्त रहा, यह धारणा शहर में व्यापक है। आलोचना का एक बड़ा बिंदु यह भी है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर जैसे संवेदनशील जिले का प्रभार ऐसे समय में अनुभवी हाथों में क्यों नहीं सौंपा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि बड़े शहरों में छोटी प्रशासनिक चूक भी बड़े हादसे का रूप ले लेती है। यदि इंदौर जिले की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता को दी जाती तो संभव है कि समय रहते चेतावनियों पर कार्रवाई होती, तकनीकी खामियों की जांच तेज होती और नागरिकों तक दूषित पानी पहुंचने से पहले ही आपूर्ति रोकी जाती।

राजनीतिक नेतृत्व के सख्ती की आवश्यकता

इस घटना ने नगर निगम अधिकारियों की कार्यप्रणाली की भी पोल खोल दी है। पाइपलाइन की निगरानी, जल शोधन संयंत्रों की नियमित जांच और शिकायतों पर त्वरित प्रतिक्रिया ये सब कागजों में तो मौजूद हैं, लेकिन जमीन पर इनकी प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि फाइलों में सब कुछ दुरुस्त दिखाया गया, जबकि वास्तविकता इससे उलट थी। यदि राजनीतिक नेतृत्व सख्त होता, नियमित समीक्षा करता और जवाबदेही तय करता, तो शायद हालात इतने भयावह न होते। इंदौर की यह त्रासदी केवल एक शहर तक सीमित नहीं है। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे अन्य बड़े शहरों के नागरिकों के मन में भी यह डर बैठ गया है कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं। शहरी जल आपूर्ति व्यवस्था में यदि यही ढीलापन और लापरवाही बनी रही, तो यह संकट किसी भी शहर में दोहराया जा सकता है। ऐसे में सवाल यह नहीं कि हादसा हुआ क्यों, बल्कि यह है कि भविष्य में इसे रोका कैसे जाए।

शहरी प्रशासन को कैलाश विजयवर्गीय ने केवल योजनाओं के भरोसे नहीं छोड़ा

कैलाश विजयवर्गीय ने अपने राजनीतिक जीवन में शहरी प्रशासन को केवल योजनाओं के भरोसे नहीं छोड़ा, बल्कि नियमित फील्ड विजिट, अधिकारियों की जवाबदेही और जनता से सीधा संवाद इन तीनों को समान महत्व दिया। इंदौर में उनके प्रभाव के दौरान शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और अफसरों पर स्पष्ट संदेश "लापरवाही बर्दाश्त नहीं" एक स्थापित कार्य संस्कृति थी। यही कारण है कि आज भी शहर का एक बड़ा वर्ग मानता है कि यदि वही मॉडल जारी रहता तो भागीरथपुरा जैसी घटना टाली जा सकती थी। आरोप यह भी है कि वर्तमान व्यवस्था में "सिस्टम लीकेज" हुआ यानी कलेक्टर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक सूचनाओं का सही और समय पर प्रवाह नहीं हुआ या हुआ तो उस पर कार्रवाई नहीं की गई। यदि यह सही है।

संवेदनशीलता और तत्परता की मिसाल बने कैलाश विजयवर्गीय

भागीरथपुरा की दर्दनाक घटना के बाद जब शहर शोक और आक्रोश में डूबा था, तब सबसे पहले मौके पर पहुँचकर पीड़ितों और मृतकों के परिजनों से मिलने वाले नेताओं में कैलाश विजयवर्गीय अग्रणी रहे। उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के सीधे प्रभावित परिवारों के घर जाकर उनसे मुलाकात की, उनकी पीड़ा सुनी और उन्हें ढांढस बंधाया। यह उपस्थिति केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का प्रतीक मानी गई। उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने, दोषियों पर सख्त कार्रवाई कराने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का भरोसा दिलाया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि संकट की इस घड़ी में विजयवर्गीय का मौके पर पहुँचना प्रशासन के लिए भी एक स्पष्ट संदेश था कि जनता की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कानून के कटघरे में सत्ता की परछाईं भूपेश बघेल, उनका परिवार और छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला

(पेज 1 का शेष)

चार्जशीट में यह दावा किया गया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के भीतर एक जबरन वसूली आधारित सिंडिकेट सक्रिय था, जिसे न केवल संगठित किया गया बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण भी मिला। आरोप है कि इस व्यवस्था के जरिए शराब लाइसेंस, वितरण और बिक्री के हर चरण से अवैध कमाई की गई। इस पूरे कथित ढांचे में चैतन्य बघेल की भूमिका केवल "लाभार्थी" तक सीमित नहीं बताई गई है, बल्कि उन्हें अपराध से अर्जित धन को "मैनेज करने वाले उच्चस्तरीय ऑपरेटर" के रूप में पेश किया गया है।

चैतन्य बघेल और 200-250 करोड़ रुपये का दावा

एसीबी और इओडब्ल्यू की सातवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अनुसार, चैतन्य बघेल को अपने हिस्से के तौर पर लगभग 200 से 250 करोड़ रुपये मिले। यह राशि केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं मानी जा रही, बल्कि यह उस नेटवर्क का हिस्सा बताई गई है, जिसके जरिए कुल अपराध आय को ऊपर तक पहुंचाया गया। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि चैतन्य ने कारोबारी अनवर ढेबर की टीम द्वारा जुटाई गई रकम को संभालने और आगे ट्रांसफर करने के लिए अपने भरोसेमंद नेटवर्क का इस्तेमाल किया। कथित तौर पर यह धन शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लो की विभिन्न फर्मों के जरिए प्राप्त हुआ और फिर बैंकिंग चैनलों के माध्यम से परिवार से जुड़े व्यवसायों तथा रियल एस्टेट वेंचर्स में निवेश किया गया। यदि ये आरोप न्यायिक प्रक्रिया में साबित होते हैं, तो यह मामला केवल भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग और राजनीतिक परिवारों के आर्थिक हितों के टकराव का गंभीर उदाहरण बन सकता है।

प्रशासनिक मशीनरी की भूमिका

ईडी की अंतिम अभियोजन शिकायत में जिन 59 नए आरोपियों के नाम जोड़े गए हैं, उनमें मुख्यमंत्री कार्यालय के तत्कालीन उप सचिव, पूर्व आईएएस अधिकारी, आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, शराब लाइसेंस धारक और वितरक शामिल हैं। यह तथ्य अपने आप में इस घोटाले की कथित व्यापकता को दर्शाता है। पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दंडात्मक कार्रवाई को रोके रखा, जिससे घोटाला बिना किसी बाधा के चलता रहा। यदि प्रशासनिक तंत्र का एक हिस्सा राजनीतिक नेतृत्व के संकेतों पर आंख मूंदकर काम करता रहा, तो यह लोकतांत्रिक शासन की मूल भावना पर सीधा आघात है।

भूपेश बघेल की राजनीतिक जिम्मेदारी

भूपेश बघेल स्वयं इस मामले में प्रत्यक्ष आरोपी नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न उनसे अलग नहीं किया जा सकता। एक मुख्यमंत्री के रूप में, आबकारी जैसा संवेदनशील विभाग उनके शासनकाल में था। यदि उसी अवधि में हजारों करोड़ रुपये के कथित घोटाले का नेटवर्क फल-फूल रहा था, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राजनीतिक नेतृत्व को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर जानबूझकर अनदेखी की गई। इसके अतिरिक्त, जब आरोप मुख्यमंत्री के बेटे पर हों और वह कथित तौर पर घोटाले की रकम के प्रबंधन में "केंद्रीय भूमिका" में बताया जाए, तो परिवार और सत्ता के बीच की रेखा और भी धुंधली हो जाती है। विपक्ष इसी बिंदु को कांग्रेस की "भ्रष्टाचार विरोधी" राजनीति के विरोधाभास के रूप में पेश कर रहा है।

3500 करोड़ के अपराध के मुखिया हैं बघेल

यह भी महत्वपूर्ण है कि अब तक लगाए गए सभी आरोप एजेंसियों के दावे हैं और अंतिम निर्णय न्यायालय को करना है। भारतीय कानून व्यवस्था में "आरोप सिद्ध होने तक निर्दोष" का सिद्धांत लागू होता है। भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी लगातार इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते रहे हैं। फिर भी, 3,000 से 3,500 करोड़ रुपये की कथित अपराध आय, आठ चार्जशीट, हजारों पन्नों के दस्तावेज, डिजिटल और बैंकिंग सबूत- ये सभी इस मामले को साधारण राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर ले जाते हैं। जांच एजेंसियों द्वारा बार-बार समान निष्कर्षों पर पहुंचना और अलग-अलग स्तर के अधिकारियों व कारोबारियों का आरोपी बनना, मामले की गंभीरता को रेखांकित करता है।

छत्तीसगढ़ की राजनीति पर प्रभाव

यह घोटाला छत्तीसगढ़ की राजनीति में लंबे समय तक असर डाल सकता है। कांग्रेस के लिए यह मामला नैतिक संकट जैसा बन गया है, खासकर तब जब पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा को घेरती रही है। दूसरी ओर, भाजपा इसे कांग्रेस शासन के "भ्रष्ट मॉडल" के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रही है। भूपेश बघेल के राजनीतिक भविष्य पर भी इसका असर पड़ना तय है। भले ही वे कानूनी रूप से दोषमुक्त साबित हों, लेकिन जनमानस में उठे सवालों और राजनीतिक विमर्श से पूरी तरह बच पाना कठिन होगा।

छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला केवल आर्थिक अपराध का मामला नहीं है; यह सत्ता, परिवार, प्रशासन और जवाबदेही के जटिल रिश्तों की कहानी है। भूपेश बघेल के शासनकाल में विकसित इस कथित तंत्र ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग अपने निकटतम लोगों की गतिविधियों से वास्तव में अनजान रह सकते हैं। अब यह जिम्मेदारी न्यायिक प्रक्रिया पर है कि वह तथ्यों और सबूतों के आधार पर सच को सामने लाए। लेकिन तब तक, यह मामला भारतीय राजनीति में यह बहस जरूर तेज करता रहेगा कि सत्ता में रहते हुए पारदर्शिता, नैतिकता और जवाबदेही को कैसे सुनिश्चित किया जाए और जब आरोप सत्ता के सबसे करीबी दायरे तक पहुंच जाएं, तो राजनीतिक नेतृत्व को किस स्तर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल, सुशासन सबसे बड़ा कारक

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। हमने देश का पहला सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया है, जो सभी योजनाओं के समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन का केंद्र है। पिछले दो वर्षों में हमने 400 से अधिक नीतिगत सुधार किए, पुराने अनुपयोगी नियम-कानून समाप्त किए और कई में संशोधन किए। इन सुधारों से प्रदेशवासियों का जीवन सरल हुआ और प्रशासन अधिक कुशल बना। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 में सुशासन एवं नवाचारों के लिए 5 विभागों एवं 5 जिलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने ई-प्रगति पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से अब छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की निगरानी की जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से निर्माण की मंजूरी से लेकर बजट, मजदूरी, भुगतान, एमआईएस, स्ट्रक्चर लेवल सहित सभी पहलुओं की मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के माध्यम से 5 जिलों और 5 विभागों के नवाचारी प्रयासों को सम्मानित किया गया है। इससे अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी प्रोत्साहित होंगे। आगामी वर्ष से 8 अलग-अलग क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिनमें ई-गवर्नेंस, सेवा वितरण, ग्रामीण और शहरी विकास जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में नवाचार और सुशासन की एक सशक्त संस्कृति विकसित हो रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शासन में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए "पहल" और "प्रेरणा" योजनाएँ प्रारंभ की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ई-प्रगति पोर्टल का किया शुभारंभ

"पहल" से नए विचारों को सहयोग मिलेगा और "प्रेरणा" से सफल योजनाओं का विस्तार होगा। शीघ्र ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी प्रारंभ की जाएगी, जिससे शिकायत निवारण और जनभागीदारी मजबूत होगी। सेवाओं की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है और लोक सेवा गारंटी अधिनियम को LSG-2.0 के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बदलते दौर में तकनीक जीवनशैली का हिस्सा बन चुकी है। इसलिए हमने डिजिटल संसाधनों की शक्ति को पहचानते हुए तकनीक को सुशासन का प्रमुख हथियार बनाया है। सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ई-ऑफिस ने सरकारी कामकाज में गति और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित की हैं। अब फाइलें हफ्तों-महीनों नहीं, बल्कि एक क्लिक पर आगे बढ़ती हैं। इससे कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो रही है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है। ई-ऑफिस मंत्रालय से प्रारंभ हुआ था और अब विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी लागू हो चुका है। आगामी कुछ महीनों में इसे सभी संभागों और जिलों में भी लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है, जिसके पीछे सुशासन सबसे बड़ा कारक है। डिजिटल भुगतान में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान भी गुड गवर्नेंस का ही परिणाम है।

उन्होंने कहा कि खनिज परिवहन की परमिट व्यवस्था को ऑनलाइन किया गया है, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगी है और विकास कार्यों के लिए संसाधनों की सुरक्षा हुई है। इसी तरह शासकीय खरीदी को जेम पोर्टल से जोड़ा गया है, जिससे पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। उन्होंने अधिकारियों को खरीदी प्रक्रियाओं में समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रजिस्ट्री विभाग में की गई 10 क्रांतिकारी पहल से अब नागरिक घर बैठे ही रजिस्ट्री कर पा रहे हैं। नई औद्योगिक नीति के तहत पिछले वर्ष 7.83 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के माध्यम से निवेशकों को तेजी से स्वीकृति और क्लियरेंस दिए जा रहे हैं। साय ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से गांव-गांव जाकर 41 लाख आवेदनों का निराकरण किया गया। यह जनभागीदारी का सशक्त उदाहरण है।उन्होंने कहा कि सांसदों और विधायकों के पत्रों और आवेदनों का समय पर निराकरण होना चाहिए। अच्छे प्रशासन के लिए संवाद, समन्वय और फीडबैक आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ-साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। सरकार के निर्णयों और उपलब्धियों का सही संचार भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अंजोर विजन के अंतर्गत 2030 तक के लक्ष्यों की समीक्षा कर प्रदेश को समृद्ध और विकसित राज्य बनाने का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है। इन सभी नवाचारों के माध्यम से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में शासन केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है, बल्कि परिणामों, प्रभाव और नागरिक विश्वास पर केंद्रित एक नई प्रशासनिक संस्कृति विकसित हो रही है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 के अंतर्गत सम्मानित ये जिले और विभाग सुशासन, पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और जनकल्याण के नए मानक स्थापित कर रहे हैं। यह उपलब्धियाँ न केवल राज्य के प्रशासनिक तंत्र की क्षमता को दर्शाती हैं, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता और भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि को भी सुदृढ़ करती हैं।

जनजातीय संस्कृति के संरक्षण में छत्तीसगढ़ की सशक्त पहल

(पेज 1 का शेष)

इस योजना के अंतर्गत जनजातीय समुदायों के पूजा स्थलों, सांस्कृतिक अखरों और पारंपरिक सभा स्थलों का विकास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना में 2 करोड़ 50 लाख रुपये का बजटीय प्रावधान किया जाना सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अखरा केवल एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि जनजातीय समाज की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र होता है। यहीं लोकनृत्य, लोकगीत, पारंपरिक अनुष्ठान और सामूहिक निर्णयों की परंपरा जीवित रहती है। मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में इन अखरों का संरक्षण और विकास जनजातीय समाज की जड़ों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

जनजातीय गौरव दिवस को मिली नई पहचान

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूरे सम्मान और उत्साह के साथ किया जा रहा है। पिछले वर्ष रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बैगा, गुनिया, सिरहा और हथजोड़ जैसे पारंपरिक जनजातीय पुरोधाओं को प्रोत्साहित करने और उनके सांस्कृतिक एवं पूजा स्थलों को अखरा विकास योजना के तहत विकसित करने का संकल्प लिया। यह पहल जनजातीय समाज के लिए केवल सम्मान का प्रतीक नहीं, बल्कि उनकी परंपराओं को जीवित रखने का सशक्त माध्यम भी बनी है।

सांस्कृतिक दलों को सीधा संबल

जनजातीय लोककलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने आदिवासी सांस्कृतिक दलों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की अभिनव व्यवस्था की है। सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों की खरीद के लिए प्रति दल 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। बीते दो वर्षों में 1180 सांस्कृतिक दल इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। इससे न केवल लोककलाओं को नया जीवन मिला है, बल्कि युवा पीढ़ी भी अपनी परंपराओं से जुड़ने के लिए प्रेरित हुई है।

आस्था और संस्कृति का संगम

आदिवासी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा देवगुड़ी होती है, जो जनजातीय समाज की सामूहिक आस्था का केंद्र है। आदिवासी संस्कृति परिरक्षण एवं विकास योजना के तहत देवगुड़ियों के निर्माण और मरम्मत के लिए प्रति स्थल 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले दो वर्षों में लगभग 800 देवगुड़ियों के लिए 15 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह पहल जनजातीय समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की दिशा में एक मजबूत आधार बनी है।

मुख्यमंत्री आदिवासी परम सम्मान निधि योजना

मुख्यमंत्री श्री साय की संवेदनशील सोच का परिचायक मुख्यमंत्री आदिवासी परम सम्मान निधि योजना है। इस योजना के माध्यम से जनजातीय तीज-त्यौहारों, उत्सवों और परंपराओं को मूल स्वरूप में संरक्षित कर अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही सांस्कृतिक परंपराओं का अभिलेखिकरण भी किया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को इसके लिए 10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। बीते दो वर्षों में 11,266 ग्राम पंचायतों को 11 करोड़ 26 लाख 60 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि से जुड़ा राज्य का संकल्प

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय समाज के उत्थान के लिए किए गए आह्वान की झलक मुख्यमंत्री श्री साय की नीतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पीएम जनमन योजना के तहत 24 हजार करोड़ रुपये और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 80 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार इन राष्ट्रीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारने में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

सम्मान निधि और स्मृति संरक्षण

मुख्यमंत्री श्री साय ने बैगा, गुनिया और सिरहा जैसे जनजातीय पुरोधाओं के लिए प्रति वर्ष 5 हजार रुपये की सम्मान निधि की घोषणा कर उनके योगदान को संस्थागत सम्मान दिया है। इसके साथ ही जनजातीय शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाएं चिन्हित स्थलों पर स्थापित करने की पहल जनजातीय इतिहास को नई पीढ़ी से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजातीय समाज के सम्मान, संरक्षण और समग्र विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया है। अखरा विकास योजना से लेकर सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण, देवगुड़ी संरक्षण और सम्मान निधि तक, ये सभी पहलें यह दर्शाती हैं कि सरकार केवल योजनाएं नहीं बना रही, बल्कि जनजातीय समाज के विश्वास और आत्मसम्मान को सशक्त कर रही है। यह मॉडल न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश के लिए जनजातीय संस्कृति के संरक्षण का एक अनुकरणीय उदाहरण बनता जा रहा है।

सम्पादकीय

अमेरिका की टैरिफ धमकी और भारत के लिए निहितार्थ

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और 2024 के बाद एक बार फिर सक्रिय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी कोई नई बात नहीं है। यह बयान ट्रंप की उसी संरक्षणवादी और आक्रामक व्यापार नीति की निरंतरता है, जिसमें "अमेरिका फर्स्ट" के नाम पर मित्र देशों पर भी दबाव बनाने से संकोच नहीं किया जाता। भारत को लेकर उनकी यह टिप्पणी न केवल द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर प्रश्न खड़े करती है, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता की ओर भी संकेत करती है। डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक स्वभाव हमेशा से ही आक्रामक और बयानबाजी पर आधारित रहा है। अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने भारत को "टैरिफ किंग" कहकर निशाना बनाया था और स्टील, एल्युमिनियम तथा कुछ अन्य उत्पादों पर शुल्क बढ़ाए थे। अब 500 प्रतिशत टैरिफ जैसी अतिरंजित धमकी दरअसल घरेलू अमेरिकी राजनीति को साधने का एक प्रयास अधिक प्रतीत होती है। अमेरिका में चुनावी माहौल में विदेशी देशों को कठघरे में खड़ा करना ट्रंप की आजमाई हुई रणनीति रही है, जिससे वे अपने मतदाताओं के बीच राष्ट्रवादी और कठोर नेता की छवि मजबूत करते हैं। भारत-अमेरिका व्यापार संबंध बीते दो दशकों में निरंतर मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार 190 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है और भारत अमेरिका के लिए एक बड़ा बाजार होने के साथ-साथ रणनीतिक साझेदार भी है। आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारतीय कंपनियों की अमेरिका में गहरी मौजूदगी है। ऐसे में 500 प्रतिशत टैरिफ जैसी धमकी व्यावहारिक कम और राजनीतिक अधिक लगती है। इतना अधिक शुल्क लगाना न केवल भारतीय निर्यातकों को प्रभावित करेगा, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए भी महंगाई बढ़ाने वाला कदम होगा। इस बयान का एक दूसरा पहलू यह भी है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (ग्लोबल सप्लाई चेन) के पुनर्संतुलन के दौर में भारत को चीन के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका की कई कंपनियां चीन से बाहर निकलकर भारत में निवेश बढ़ा रही हैं। ऐसे समय में भारत पर कठोर टैरिफ की बात करना अमेरिकी आर्थिक हितों के भी विरुद्ध जाता है। यही कारण है कि ट्रंप के ऐसे बयानों को अमेरिकी प्रशासनिक तंत्र और उद्योग जगत अक्सर गंभीरता से नहीं लेता।

भारत के दृष्टिकोण से देखें तो यह चुनौती के साथ-साथ अवसर भी है। भारत को अब यह स्पष्ट समझ में आ चुका है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में केवल मित्रता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। भारत ने बीते वर्षों में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और निर्यात विविधीकरण पर जोर देकर अपनी स्थिति मजबूत की है। यूरोप, अफ्रीका, मध्य-पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार बढ़ाकर भारत ने किसी एक बाजार पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। कूटनीतिक स्तर पर भारत की परंपरा रही है कि वह उकसावे में आकर प्रतिक्रिया नहीं देता। ट्रंप की इस धमकी पर भी भारत को संयम और रणनीतिक धैर्य के साथ जवाब देना होगा। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों, द्विपक्षीय संवाद और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। इसके साथ ही घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना और वैल्यू एडिशन पर ध्यान देना समय की मांग है। अंततः, डोनाल्ड ट्रंप की 500 प्रतिशत टैरिफ की धमकी एक राजनीतिक बयान से अधिक कुछ नहीं दिखती। यह बयान वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं और परस्पर निर्भरता को नजरअंदाज करता है। भारत आज पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वासी और सक्षम अर्थव्यवस्था है। ऐसे में इस तरह की धमकियां भारत की दिशा तय नहीं कर सकतीं। जरूरत है सतर्क कूटनीति, मजबूत घरेलू नीति और वैश्विक मंचों पर आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने की। यही भारत के दीर्घकालिक हित में है।

सियासी गहमागहमी

अपनी उपलब्धियों को गिनाने में मशगूल मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इन दिनों जमीनी कार्यों से अधिक मंचों और माइकों पर उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त गिनाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। हर कार्यक्रम, हर लोकार्पण और हर भाषण में विकास की ऐसी तस्वीर पेश की जाती है, मानो प्रदेश की सारी समस्याएं फाइलों के साथ-साथ जमीन से भी उठकर हवा में घुल चुकी हों। सड़कों के गड्ढे, पेयजल की किल्लत, स्वास्थ्य और शिक्षा की जमीनी चुनौतियां शायद अभी "अगले चरण" में हों, लेकिन उपलब्धियों का प्रचार वर्तमान काल में पूरे आत्मविश्वास से चल रहा है। सरकार की प्रेस विज्ञप्तियों में प्रदेश हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, मगर आम नागरिक रोजमर्रा की दिक्कतों से जूझते हुए सोच रहा है कि ये ऊंचाइयां आखिर किस नक्शे पर दर्ज हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि योजनाएं पहले पोस्टर पर उतरती हैं, फिर भाषणों में परिपक्व होती हैं और अंत में जमीन तक पहुंचने के लिए लंबी प्रतीक्षा करती हैं। मुख्यमंत्री की शैली में "हम करेंगे" और "हमने कर दिया" के बीच की दूरी लगातार सिमटती जा रही है, भले ही जनता को उसका अनुभव न हो। उपलब्धियों की गिनती इतनी तेज है कि जमीनी काम शायद दौड़ में पीछे छूट गए हैं। यदि यही रफ्तार रही, तो संभव है कि समस्याएं खुद थककर समाधान ढूंढ लें और सरकार उन्हें भी एक और उपलब्धि के रूप में गिना दे।

बाबर के कार्यों पर मूकदर्शक बना संस्कृति विभाग

मध्यप्रदेश की धरती पर इन दिनों इतिहास अचानक बहुत जाग गया है खासतौर पर बाबर को लेकर। दिलचस्प यह है कि यह जागरण सत्ता के गलियारों और मुख्यमंत्री निवास के आस्पास तो साफ दिखाई देता है, लेकिन प्रदेश का संस्कृति विभाग गहरी निद्रा में लीन नजर आता है। मानो इतिहास पर चर्चा करना केवल बयानबाजी का विषय हो, शोध, विमर्श और सांस्कृतिक दृष्टि उसकी जिम्मेदारी न हो। जब-जब बाबर का नाम आता है, तब-तब राजनीति में ऊर्जा का संचार हो जाता है। टीवी डिबेट से लेकर भाषणों तक इतिहास का ऐसा पुनर्लेखन होने लगता है, जैसे अगले अध्याय की परीक्षा कल ही हो। लेकिन जिन संस्थानों का काम है इतिहास को संतुलित, तथ्यपरक और सांस्कृतिक संदर्भों में प्रस्तुत करना। वे खामोशी की समाधि में हैं। संस्कृति विभाग शायद इस भ्रम में है कि इतिहास अपने आप संभल जाएगा या फिर यह विषय केवल राजनीतिक मंचों के लिए आरक्षित है। मुख्यमंत्री निवास के पास इतिहास पर चर्चा गरम है, पर उसी सरकार का संस्कृति विभाग ठंडा पड़ा है। न कोई संगोष्ठी, न कोई शोध संवाद, न ही कोई सार्वजनिक विमर्श। यदि यही स्थिति रही तो आने वाली पीढ़ियां इतिहास किताबों से नहीं, बल्कि भाषणों की कटिंग से सीखेंगी। और तब संस्कृति विभाग शायद यह उपलब्धि भी गिनाएगा कि उसने इतिहास पर "मौन साधना" का विश्व रिकॉर्ड बनाया।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

देश भर में "भ्रष्ट" जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है।

भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर BJP की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है।

इनके सिस्टम में गरीब, असहाय, मजदूर और मध्यमवर्ग की जिंदगी सिर्फ़ आंकड़ा है और "विकास" के नाम पर वसूली-तंत्र चल रहा है।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

भाजपा हमेशा डबल इंजन सरकार का ढोल पीटती है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में ढोल की पोल खुल गई।

चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार से प्रदेश को 44 हजार करोड़ रुपए मिलने थे लेकिन अब तक मुश्किल से 10 हजार करोड़ रुपए ही मिले हैं।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

राजनीति, पत्रकारिता और क्रिकेट प्रशासन की त्रिवेणी है राजीव शुक्ला

समता पाठक/जगत प्रवाह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अनुभवी सांसद और भारतीय राजनीति में संतुलित व वैचारिक आवाज के रूप में पहचाने जाने वाले राजीव शुक्ला का जीवन बहुआयामी व्यक्तित्व का उदाहरण है। राजनीति, पत्रकारिता और क्रिकेट प्रशासन- तीनों क्षेत्रों में उनकी सक्रिय और प्रभावी भूमिका रही है। सहज, सौम्य और संवादप्रिय स्वभाव के कारण वे सत्ता और संगठन, दोनों स्तरों पर सम्मानित माने जाते हैं। राजीव शुक्ला का जन्म 13 सितंबर 1959 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की, लेकिन उनका रुझान प्रारंभ से ही सार्वजनिक जीवन और लेखन की ओर था। छात्र जीवन में ही वे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सक्रिय हो गए थे। पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने अपनी वैचारिक यात्रा की शुरुआत की, जिसने आगे चलकर उन्हें राजनीति के शीर्ष मंच तक पहुंचाया।

पत्रकारिता के क्षेत्र में राजीव शुक्ला ने उल्लेखनीय पहचान बनाई। उन्होंने जनसत्ता, नवभारत टाइम्स और रविवार जैसी प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में कार्य किया। राजनीतिक रिपोर्टिंग और विश्लेषण में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती थी। टेलीविजन के आरंभिक दौर में वे राजनीतिक कार्यक्रमों और विमर्श का जाना-पहचाना चेहरा बने। पत्रकार के रूप में उन्होंने सत्ता के गलियारों को करीब से देखा और समझा, जिसका लाभ उन्हें बाद में राजनीतिक जीवन में मिला। वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत में राजीव शुक्ला ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। उनकी वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक समझ और संवाद कौशल के चलते वे शीघ्र ही पार्टी नेतृत्व के विश्वासपात्र बन गए। वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुने गए और संसद के भीतर अपनी सधी हुई, तथ्यों पर आधारित और संतुलित वक्तव्यों के लिए पहचाने गए। संसदीय बहसों में उनकी भाषा आक्रामक नहीं, बल्कि तर्कपूर्ण और संवादपरक रही है।

कांग्रेस संगठन में राजीव शुक्ला ने विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। वर्तमान में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। संगठन में उनकी भूमिका एक ऐसे नेता की रही है जो विभिन्न गुटों के बीच सेतु का काम करता है। पार्टी की रणनीति, मीडिया समन्वय और संसदीय मामलों में उनकी सलाह को महत्व दिया जाता है। वे कांग्रेस के उन नेताओं में गिने जाते हैं जो सार्वजनिक मंचों पर संयम और गरिमा के साथ पार्टी का पक्ष रखते हैं। राजनीति के साथ-साथ राजीव शुक्ला का नाम भारतीय क्रिकेट प्रशासन से भी जुड़ा रहा है। वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। क्रिकेट प्रशासन में रहते हुए उन्होंने खेल को पारदर्शिता, व्यावसायिकता और खिलाड़ियों के हितों के दृष्टिकोण से देखने की बात कही। खेल और राजनीति के संतुलन को लेकर उनके विचार हमेशा स्पष्ट रहे हैं।

राजीव शुक्ला की पहचान केवल पदों से नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व से भी बनती है। वे विवादों से दूरी बनाकर रखने वाले नेता माने जाते हैं। मीडिया से संवाद में वे तथ्यों और मर्यादा का ध्यान रखते हैं। यही कारण है कि वे अक्सर पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता की भूमिका में भी दिखते हैं, जहां वे विपक्ष के सवालों का जवाब संयम और तर्क के साथ देते हैं। व्यक्तिगत जीवन में राजीव शुक्ला सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी अनुराधा प्रसाद एक जानी-मानी पत्रकार और मीडिया उद्यमी हैं, जिनका भी मीडिया जगत में विशेष स्थान है। पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक जीवन के बीच संतुलन उनकी जीवनशैली का अहम हिस्सा रहा है। कुल मिलाकर, राजीव शुक्ला का जीवन पत्रकारिता की निर्भीकता, राजनीति की परिपक्वता और प्रशासनिक अनुभव का समन्वय है। वे कांग्रेस के उन नेताओं में हैं जो शोर से अधिक संवाद में विश्वास रखते हैं। बदलते राजनीतिक दौर में भी उनकी भूमिका एक ऐसे नेता की बनी हुई है, जो विचार, विवेक और वैचारिक संतुलन के साथ सार्वजनिक जीवन में सक्रिय है।

स्वामी विवेकानंद की जयंतीः उत्सव और आत्ममंथन के बीच देश

भटकाव की डगर पर 'भविष्य' का भारत

आज की बात

प्रवीण कक्कड़

स्वतंत्र लेखक

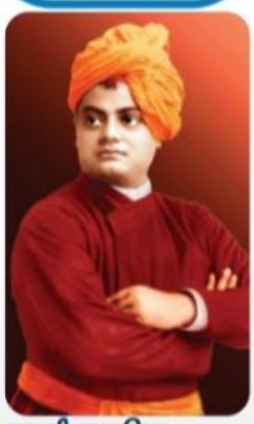

पूरा देश 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाता है। आज स्वामी जी के बारे में सोचते हुए वर्तमान पीढ़ी को लेकर कई प्रश्न मन में उठते हैं। 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जिस तरुण संन्यासी ने भारत की आध्यात्मिक गरिमा को विश्व के हृदय तक पहुँचाया था, उनकी स्मृति आज भी हमारी राष्ट्रीय चेतना को गौरवान्वित करती है। लेकिन उत्सव की इस रोशनी के बीच एक धुंधला, पर बेहद जरूरी प्रश्न हमारे सामने खड़ा है क्या हम स्वामीजी के विचारों को जी रहे हैं, या केवल उनकी स्मृति का अनुष्ठान कर रहे हैं?

आज का युवा - जिसे विवेकानंद "राष्ट्र का निर्माता" कहते थे क्या सच में निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, या आधुनिकता की चकाचौंध में अपनी ऊर्जा का विसर्जन कर रहा है? यह समय केवल जयघोष का नहीं, बल्कि गहरे आत्ममंथन का है कि हम अपनी भावी पीढ़ी को केवल ऊँचे सपने थमा रहे हैं या उन्हें उन सपनों तक पहुँचने का सही मार्ग भी दिखा पा रहे हैं।

क्षमता का नहीं, बल्कि दिशा का संकट

युवा शक्ति का वर्तमान संकट क्षमता का नहीं, बल्कि दिशा का है। आज के युवा के पास अपार क्षमता है; शिक्षा, तकनीक और अवसर सब कुछ उसके पास है, परंतु 'दृष्टि' की कमी सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही है। स्वामी विवेकानंद ने भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाने का आह्वान किया था, लेकिन आज वह शक्ति सोशल मीडिया की आभासी चमक, क्षणिक आकर्षणों और उपभोक्तावादी दौड़ में कहीं खोती जा रही है। विडंबना यह है कि जिस पीढ़ी के पास उंगलियों पर पूरी दुनिया का ज्ञान उपलब्ध है, वही पीढ़ी अपने भीतर के खालीपन को नशे, देर रात की पार्टियों और अनुशासनहीन जीवनशैली से भरने की कोशिश कर रही है। जिसे वे आधुनिकता समझ रहे हैं, वह प्रगति नहीं, बल्कि संस्कारों से कटकर एक लक्ष्यहीन भीड़ का हिस्सा बन जाना है। यही वह 'मानसिक दरिद्रता' है, जिसे स्वामी जी ने सांस्कृतिक पतन की संज्ञा दी थी।

हमारी सामूहिक विफलता

यहाँ दोष केवल युवाओं का नहीं, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, परिवार और समाज की सामूहिक विफलता पर भी है। हमने उन्हें 'सफल' होने की कला तो सिखाई, पर 'सार्थक' होने का विज्ञान नहीं सिखाया। हमने उन्हें गलाकाट प्रतियोगिता की दौड़ में धकेला, पर गिरकर संभलने का आत्मबल नहीं दिया। स्वामी जी ने युवाओं के लिए तीन आधारभूत स्तंभ बताए थे- शक्ति, आत्मविश्वास और चरित्र। आज हमारे पास भौतिक संसाधन तो हैं, पर मानसिक दुर्बलता बढ़ रही है; हाथों में डिग्रियाँ तो हैं, पर चरित्र निर्माण की पाठशालाएँ सूनी पड़ी हैं। प्रश्न यह है कि क्या हम केवल उपदेश दे रहे हैं, या अपने उदाहरणों से उन्हें प्रेरित भी कर रहे हैं? समाज को यह समझना होगा कि युवा केवल सलाह से नहीं, बल्कि सही आदर्शों को देखकर बदलते हैं।

'उठो, जागो' आज अधिक प्रासंगिक

'उठो, जागो' स्वामी विवेकानंद का यह मंत्र आज इसलिए और अधिक प्रासंगिक है क्योंकि आज की नींद आँखों की नहीं, बल्कि चेतना की है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को 'पुरातन' नहीं, बल्कि 'अनंत और आधुनिक' बताया था, एक ऐसी संस्कृति जो समय के साथ स्वयं को परिष्कृत करती है, पर अपने मूल मूल्यों से विचलित नहीं होती। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी क्रांति के युग में हैं, तब यह समझना आवश्यक है कि तकनीक मात्र एक साधन है, समाधान नहीं। समाधान तो केवल मानवीय मूल्यों और सुदृढ़ चरित्र में ही निहित है। यदि युवा अपनी ऊर्जा को रचनात्मकता के बजाय व्यर्थ के विवादों, गलत आदतों और दिखावटी आधुनिकता में नष्ट करेंगे, तो 'जनसांख्यिकीय लाभांश' का हमारा गौरव 'जनसांख्यिकीय संकट' में बदलते देर नहीं लगेगी।

युवाओं को संवाद की जरूरत

राष्ट्रीय युवा दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि राष्ट्र के पुनरुद्धार का दायित्व है। युवाओं को आज कठोर आदेशों की नहीं, बल्कि संवाद की जरूरत है; उन्हें नियमों की बेड़ियों की नहीं, बल्कि सही दिशा की आवश्यकता है। हमें उन्हें यह समझाना होगा कि अनुशासन कोई बंधन नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। भारत तभी 'विश्वगुरु' बनेगा, जब उसका युवा डिजिटल स्क्रीन के मोहपाश से बाहर निकलकर धरातल की चुनौतियों से टकराएगा और अपने चरित्र की शुचिता से समाज को आलोकित करेगा। अंत में, यह प्रश्न हम सबके लिए है क्या हम अपने युवाओं को केवल एक 'बाजार' दे रहे हैं या एक संस्कारित राष्ट्र? क्या हम उन्हें सिर्फ सपनों के पंख दे रहे हैं या उन तूफानों से लड़ने का साहस भी, जिनसे टकराकर महापुरुषों का निर्माण होता है? युवा केवल भविष्य नहीं, वर्तमान की जीवित शक्ति हैं; और जब इस शक्ति का संगम संयम, चरित्र और कर्तव्य से होता है, तभी इतिहास के नए अध्याय लिखे जाते हैं।

अमेरिका की बेलगामी के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र की लाचारी

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सेलिया फ्लोरेस का अमेरिका द्वारा किए अपहरण और गिरफ्तारी ने महाकवि तुलसीदास की इस कहावत 'समरथ को नहीं दोष गुसाईं' को चरितार्थ कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहे जिन कुतर्कों को तर्क बताकर अपने हठ को सच बताते रहें, वास्तविकता यही है कि इस कार्यवाही को किसी भी कानून के परिप्रेक्ष्य में तर्कसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है? वेनेजुएला के पक्ष में आवाज उठाने वाले दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की आपात बैठक भी हुई, जिसमें अमेरिका ने अपना पक्ष रखा और अपने तानाशाही रवैये को जायज ठहराया। हालांकि चीन ने अमेरिका की इस सैन्य कार्यवाही को सीधे-सीधे दादागिरी बताया। रूस ने भी आपत्ति जताई है। लेकिन बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस इस घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताने के अलावा अमेरिका के विरुद्ध कोई भी कड़ी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य में लाचार नजर आए। गुटेरस ने कहा कि यह सैन्य कार्यवाही क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रभुत्व के लिए चेतावनी है। इस कार्यवाही में अंतरराष्ट्रीय कानूनों और नियमों का पालन नहीं किया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, किंतु इसकी अनदेखी की गई। वेनेजुएला के प्रतिनिधि ने अमेरिका द्वारा किए इस हमले को अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों और तेल को प्राप्त करना बताया। ऐसी ही निंदा रूस, चीन, मैक्सिको, क्यूबा और कई देशों ने अमेरिका की कड़ी आलोचना की, किंतु अमेरिका के मित्र देश उसके साथ खड़े दिखाई दिए हैं।

दुनिया के तेल भंडार का 18.17 प्रतिशत तेल अर्थात 303 अरब बैरल तेल और दुर्लभ खनिज के भंडार वेनेजुएला की धरती में समाए हुए हैं। किंतु उसके पास कच्चे तेल को शोधन करने के तकनीकि संसाधन नहीं है। इसलिए इस तेल को ईंधन में नहीं बदल पा रहा है। इस तेल को शोधन के लिए जब मादुरो ने चीन से तेल और रूस से हथियार खरीदने की नीति को अंजाम दिया तो ट्रंप की नाराजी बढ़ गई और मादुरो और उनकी पत्नी सेलिया का अपहरण कर लिया। इस अपहरण की घटनाक्रम को लेकर मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा ने कहा है कि इतिहास बताएगा कि हमारे भीतर के लोगों ने किस तरह से गद्दारी करते यह राष्ट्रघात किया? मीडिया द्वारा ऐसी जानकारियां सामने लाई गई है कि वेनेजुएला सरकार में काम कर रहें लोगों ने ही उपहारों के लालच में आकर अमेरिकी सेना को राष्ट्रपति मादुरो के आवास तक पहुंचाने में मदद की है। हालांकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अमेरिका में मानक पदार्थों की तस्करी अमेरिका में करने का हवाला देकर इस सैन्य कार्यवाही को जायज ठहराया है। मादुरो को अमेरिकी कानून केर-फ्रिस्बी के तहत पकड़ा गया है। यह कानून अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद-2 के तहत राष्ट्रपति को गैर-कानूनी तरीकों से ऐसे लोगों और भागोड़ों को पकड़ने की अनुमति देता है, जो अमेरिका को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हों। इसमें प्रावधान है कि गिरफ्तारी का तरीका कितना भी गैर-कानूनी हो, एक बार अमेरिका में लाने के बाद अमेरिकी अदालत में मामला चलाया जा सकता है। इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। मादुरो पर मादक पदार्थ तस्करी के अपराधिक मामले अमेरिका में दर्ज हैं। इनमें कम से कम 20 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है।

अमेरिका ऐसा दुस्साहस 1990 में पनामा के तानाशाह मैनुअल नोरिएगा को गिरफ्तार करके दिखा चुका है। इन्हें अमेरिकी अदालत ने 40 साल की सजा सुनाई थी, किंतु 2011 में रिहा कर दिया गया था। यदि मादुरो को सजा सुनाई जाती है तो ट्रंप के राष्ट्रपति नहीं रहने के बाद कोई दूसरा राष्ट्रपति मादुरो को क्षमादान दे सकता है। खुद ट्रंप होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति हर्नांडेज को 2025 में माफी दे चुके हैं। अमेरिका कभी मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी का बहाना ढूंढकर अपने शत्रु राष्ट्रों के मुखियाओं को सबक सिखाता रहा है। 2003 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश सरकार ने ईराक पर जैविक और रासायनिक हथियार होने का दावा कर ईराक को नेस्तनाबूद कर दिया था। वहां के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को भी अपदस्थ कर दिया था। इसी तरह 2011 में अमेरिका और नाटो ने लीबिया और सीरिया में भी सैन्य हस्तक्षेप कर वहां की वर्तमान सरकारों को अपदस्थ कर दिया था। इन हस्तक्षेपों के चलते आज भी इन देशों में गृहयुद्ध एवं अस्थिरता के हालात बने हुए हैं। यही हश्र अब वेनेजुएला का होना निश्चित है। अमेरिका के सरकारी शोध संस्थान कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार 1798 से लेकर अब तक अमेरिका 469 सैन्य हस्तक्षेप दुनिया में इसलिए कर चुका है, जिससे उसे महाशक्ति माना जाता रहे।

दुनिया में लगातार ऐसे हालातों की निर्मिति सामने आने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र की कार्य-संस्कृति लाचार बनी हुई है। उस पर निरंतर प्रश्नचिन्ह उठ रहे हैं। अतएव यदि यह वैश्विक संस्था अपने भीतर समयानुकूल सुधार नहीं लाती है तो कालांतर में महत्वहीन होती चली जाएगी और फिर इसके सदस्य देशों को इसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। भारत जैसे देश को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता से बाहर रखते हुए इस संस्था ने जता दिया है कि वहां चंद अलोकतांत्रिक या तानाशाह की भूमिका में आ चुके देशों की ही तूती बोलती है। संयुक्त राश्ट्र की उम्र लंबी हो चुकने के बावजूद इसके मानव कल्याण से जुड़े लक्ष्य अधूरे हैं। इसकी निश्पक्षता भी संदिग्ध है। इसीलिए वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र ताकतवर देशों की मनमानी रोकने, शांति स्थापित करने और आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांतिप्रिय देशों के संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का गठन हुआ था। इसका अहम मकसद भविष्य की पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका और आतंकवाद से सुरक्षित रखना था। इसके सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को स्थायी सदस्यता प्राप्त है। याद रहे चीन जवाहरलाल नेहरू की अनुकंपा से ही सुरक्षा परिषद का सदस्य बना था। जबकि उस समय अमेरिका ने सुझाया था कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में लिया जाए और भारत को सुरक्षा परिषद की सदस्यता दी जाए। लेकिन अपने उद्देश्य में परिषद को पूर्णतः सफलता नहीं मिली। भारत का ऑपरेशन सिंदूर समेत तीन बार पाकिस्तान और एक बार चीन से युद्ध हो चुका है। इराक और अफगानिस्तान, अमेरिका और रूस के जबरन दखल के चलते युद्ध की ऐसी विभीषिका के शिकार हुए कि आज तक उबर नहीं पाए हैं। रूस और यूक्रेन तथा इजराइल एवं फिलीस्तान के बीच युद्ध एक नहीं टूटने वाली कड़ी बन गया है। अनेक इस्लामिक देश गृह-कलह से जूझ रहे हैं। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान बेखौफ परमाणु युद्ध की धमकी देते रहते हैं। दुनिया में फैल चुके इस्लामिक आतंकवाद पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन में लगा चीन किसी वैश्विक पंचायत के आदेश को नहीं मानता।

संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यूनिसेफ और शांति सेना जैसे संगठन काम करते हैं। लेकिन चंद देशों की ताकत के आगे ये संगठन नतमस्तक होते दिखाई देते हैं। इसीलिए शांति सेना की विश्व में बढ़ते सैनिक संघर्षों के बीच कोई निर्णायक भूमिका दिखाई नहीं दे रही है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जरूर युद्ध में अत्याचारों से जुड़े कई दशकों पुराने अंतरराष्ट्रीय विवादों में न्याय देता दिख जाता है। परंतु संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक संगठन जी- 20, जी-8, आसियान और ओपेक जैसे संगठन विभाजित दुनिया के क्रम में लाचारी का अनुभव कर रहे है। अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों द्वारा इन्हें दी जाने वाली आर्थिक मदद में कटौती कर दिए जाने के कारण भी उनका भविष्य संकट में है। इन सब खतरों के चलते इस वैश्विक मंच की विश्वसनीयता संकट में है, लिहाजा इसमें पर्याप्त सुधारों की तत्काल जरूरत तो है ही, वेनेजुएला के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसा करना जरूरी है, जिससे इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा के प्रति सदस्य देशों में विश्वास पैदा करे।

प्रकृति से ही पवित्र है जीवन हमारा

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद

भागदौड़ भरे जीवन में लोग इतने व्यस्त होते हैं कि ईश्वर की अनुपम कृति प्रकृति से अंजान रहते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि व्यक्ति प्रकृति के जितना समीप होता है सुख का सूर्योदय उतनी ही शीघ्रता से उगता प्रतीत होता है। आजकल लोग क्रोधी स्वभाव के बनते जा रहे हैं, इसका कारण ही यह है कि वे प्रकृति से दूर हो गए हैं। बहुत कम व्यक्ति अब प्रकृति के परिवर्तन को महसूस करते हैं या आनंद लेते हैं। बचपन इसलिए आनंद में बीतता है क्योंकि हम उस कालखंड में प्रकृति से जुड़े रहते हैं। बरसात में बच्चे भीगना चाहते हैं या हाथों को फैलाकर बूंदों को महसूस करते हैं। तितलियों के पीछे भागते हैं, पेड़ों पर उतरते हैं, चढ़ते हैं। इस तरह प्रकृति से तालमेल बनाकर इसका आनंद लेते हैं। लेकिन बड़े होने पर समाज की चुनौतियां भर दी जाती है, और हम सफलता असफलता के चक्कर में में फंसते चले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि प्रकृति के इस आनंद से वंचित रह जाते हैं।

हमारा उद्देश्य प्रकृति के साहचर्य मे रहकर आनंद लेने का प्रयास होना चाहिए जैसे पेड़ पौधों को आलिंगन में लेकर, पशुओं के संपर्क में रहकर या खुली आंखों से हरियाली को देखकर आदि। प्राकृतिक दृश्यों को निहारकर भी हम पोषण पा सकते हैं। यह फिलाडेल्फिया के एक अस्पताल में पर्यावरण मनोविज्ञान को लेकर एक शोध से पता चलता है। जिसमें कुछ ऐसे रोगियों को लिया गया जिन्हें पित्ताशय की बीमारी थी। सभी की एक ही स्थिति थी। कुछ रोगियों को एक ऐसे कमरे में रखा गया था जहां से सिर्फ ईंटों से बनी इमारतें दिखती थीं एवं कुछ ऐसे रोगियों को रखा गया था जहां से सिर्फ पेड़ पौधे दिखते थे। शोध में पाया गया कि जिन लोगो को पेड़ पौधे दिखते थे वे जल्द ठीक हो गए जबकि ईंटों की बनी इमारतें देखने वालों की बीमारी देर से ठीक हुआ। इससे यह पता चला कि हरियाली देखने मात्र से "हीलिंग प्रोसेस" बढ़िया रहा। तभी तो प्रकृति को "मदर नेचर" कहा जाता है। यह धरती हमारी मां है और अस्तित्व का कारण भी है। हमें पोषित करने के लिए यह धरती प्रकृति के जरिए हर वो चीज हम तक पहुंचाती है जिसकी हमें जरूरत होती है। पृथ्वी जननी है तो प्रकृति पोषक है।

अच्छा यही है कि हम प्रकृति की गोद में फले फूलें। इसके लिए ध्यान रखना होगा कि हम अपने आस पास के वातावरण को सुरम्य और सौम्य बनाएं। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन से स्पष्ट किया है कि जो स्थान प्राकृतिक संपदा से भरपूर है, जहां हरियाली, नदी, तालाब है और प्रदुषण से मुक्त है वहां जाने पर अपने व्यवहार में सौम्यता एवं मन में प्रसन्नता अनुभव किया जा सकता है। प्रकृति से जुड़ने के और भी उपाय हैं जैसे हमें सूरज, हवा, धरती, आकाश से जुड़ना चाहिए। माना जाता है कि सुबह सूरज के सामने आने से हमसे जुड़ी नाकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती है। उसी प्रकार भवन से बाहर जा कर अपनी त्वचा पर हवा के स्पर्श को महसूस करना चाहिए। यह शरीर और मस्तिष्क को आराम देता है। धरती से जुड़ने के लिए नंगे पांव घास या रेत पर चलना चाहिए। इससे अपने जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस होता है। आकाश से जुड़ने पर खुलेपन की भावना विकसित होता है। इसी प्रकार बादल, चांद, तारों पेड़ पत्तों से भी जुड़ने की अवश्यकता है। हमारे अधिकतर पर्व त्योहार भी पर्यावरण और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति के आंगन में ऊर्जा का महान भंडार संचित है। हमे स्वस्थ शरीर के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है वह प्रकृति से ही प्राप्त होती है। जो व्यक्ति प्रकृति के संपर्क में रहकर जितनी अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है वह उतना ही अधिक स्वस्थ और दीर्घायु रहता है।

मुख्यमंत्री धामी ने दिया विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 227.73 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत रोडी बेलवाला क्षेत्र पुनरूद्धार विकास कार्य हेतु 59.11 करोड की योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा गैरसैण (चमोली) विधानसभा परिसर, भराड़ीसैण में सम्पूर्ण चाहरदीवारी एवं मुख्य गेट के निर्माण कार्य हेतु वास्तविक लागत 9.87 करोड के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में 40 प्रतिशत अर्थात् 3.95 करोड की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत राज्य को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की 09 योजनाओं हेतु आवास विभाग, उत्तराखण्ड को आवंटित धनराशि 164.67 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

इस धनराशि का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की स्वीकृतिः मुख्यमंत्री धामी ने सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे स्वायत्तशासी संस्थाओं यू-कॉस्ट एवं यू-सैक के नियमित कार्मिकों के लिए महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर दिनांक 01 जनवरी, 2025 से 55 प्रतिशत तथा 01 जुलाई, 2025 से 58 प्रतिशत किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

बरमान मेला व मकर संक्रांति को लेकर जिले में सुरक्षा सख्त, होटल, लॉज, होम-स्टे व धर्मशालाओं में सघन चैकिंग के आदेश

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। बरमान मेले एवं मकर संक्रांति पर्व के दौरान जिले में सुरक्षा व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। आगामी त्योहारों, वीआईपी भ्रमण एवं संभावित सुरक्षा अलर्ट को दृष्टिगत रखते हुए असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिले की सीमांतर्गत स्थित समस्त होटल, लॉज, होम-स्टे, गेस्ट हाउस एवं धर्मशालाओं में सघन जांच एवं निगरानी के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार किसी भी अतिथि को बिना वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र—जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा पासपोर्ट

के कमरा आवंटित नहीं किया जाएगा। सभी संस्थानों को ठहरने वाले व्यक्तियों के पहचान पत्र की छायाप्रति संधारित करने एवं पृथक पंजी में उनका समुचित विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि होटल, लॉज एवं अन्य अस्थायी निवास स्थलों के प्रवेश, निकास एवं लॉबी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे चालू स्थिति में होना चाहिए तथा कम से कम 30 दिनों का वीडियो बैकअप सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। संदिग्ध बैग या भारी सामान लेकर आने वाले व्यक्तियों की मैन्युअल अथवा मेटल डिटेक्टर से जांच सुनिश्चित की जाएगी। होटल एवं आवासीय संस्थानों के प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, व्यक्ति अथवा लावारिस वस्तु की सूचना तत्काल डायल-112 या नजदीकी पुलिस चौकी को दें। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा संस्थान के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य युक्तियुक्त प्रावधानों के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संबंधित संस्थान का लाइसेंस निरस्त किया जाना भी शामिल है। जिला प्रशासन ने सभी होटल एवं आवासीय संस्थानों से आदेशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है।

नपा ने कराई पेयजल टंकियों की सफाई, नपाध्यक्ष और सीएमओ ने किया निरीक्षण, पेयजल सप्लाई को लेकर नपा अलर्ट

-नरेंद्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। नगर में पेयजल सप्लाई को लेकर नगरपालिका की टीम अलर्ट है। नगर की समूची पेयजल टंकियों की सफाई कराई जा रही है। इससे पूर्व फिल्टर प्लांट की सफाई कराई गई थी और लीकेज

पाइप लाइन बंद की जा रही है। अभी तक नगर की 12 टंकियां साफ की जा चुकी है। जल प्रदाय शाखा प्रभारी उपयंत्री अंबक पाराशर ने बताया कि नगरपालिका द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष नीतू यादव एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले के निर्देश पर समूचे नगर की टंकियों की सफाई अभियान जारी है। आज नपाध्यक्ष और सीएमओ द्वारा वार्ड क्रमांक 23 रामनगर में चल रहे सफाई कार्य का निरीक्षण किया गया। नपा द्वारा पेयजल टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। पाराशर ने बताया कि रामनगर टंकी, सरस्वती नगर की टंकी, ट्रेंचिंग ग्राउंड की टंकी, ग्वालटोली की 7 नंबर की टंकी, भीलपुरा, चर्च टंकी, हर्णे कालोनी, विश्वकर्मा मंदिर टंकी, अफिसर क्लब की टंकी, फेफरताल टंकी, छोटी पहाड़िया की टंकी, भारत माता पार्क की टंकी की सफाई गई है। साथ ही वाटर टेस्टिंग का कार्य भी किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान सहायक सुनील राठौर, सुपरवाईजर नीतेश व्यास आदि उपस्थित रहे।

संगठन की मजबूती को लेकर पूर्व केबिनेट मंत्री हर्ष यादव की संगठनात्मक बैठक, क्षेत्र में बढते अपराधों को लेकर एसडीओपी देवरी को ज्ञापन सौंपा

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरी। देवरी स्थित कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवरी द्वारा पूर्व केबिनेट मंत्री हर्ष यादव नेतृत्व में विधानसभा प्रभारी तनचन्द्र जैन की अध्यक्षता में ब्लॉक देवरी, गौरझामर, महाराजपुर एवं अनंतपुरा की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से 'बूथ चलो–गांव चलो अभियान' को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने, 'मनरेगा बचाओ अभियान' के माध्यम से श्रमिकों और ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा करने तथा ग्राम पंचायत कमेटी एवं वार्ड कमेटियों के गठन को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण ग्रामीण अंचल में रोजगार, विकास एवं मूलभूत सुविधाओं की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। देवरी विधानसभा क्षेत्र के 4 थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बिगडती स्थिति,बढते अपराधो नशीले पदार्थो की तस्करी,युवाओं में बढती ड्रग्स की लत,मंदिरो में चोरी की गई घटनाओं एवं महिला अपराधो में हो रही लगातार बृद्धि के संबंध में ब्लॉक कांग्रेस देवरी के द्वारा पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में पुलिस महानिर्देशक भोपाल के नाम थाना प्रभारी देवरी को ज्ञापन सौपा, कार्यक्रम में पूर्व मंत्री हर्ष यादव,बिधानसभा प्रभारी रतनचन्द्र जैन,ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवरी आशीष वाया राजौरिया,उपब्लॉक महाराजपुर अध्यक्ष अमित सिरवैया,गौरझामर उपब्लॉक अध्यक्ष श्रीमति जानकी बीरेन्द्र लोधी,नगर कांग्रेस देवरी अध्यक्ष गौरव पाण्डेय,रजनीश जैन,आंचल आठया, सौरभ नामदेव, शुभम मिश्रा,रामेश्वर पटैल कपिल पाण्डेय, सहित कांग्रेस परिवार के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी, ब्लॉक, उपब्लॉक, मंडल, सेक्टर, बूथ स्तर के कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई तथा संगठन को आगामी आंदोलनों एवं कार्यक्रमों के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया गया।

अन्नदाता

मध्यप्रदेश शासन

पराली न जलाएं, धरती और जीवन बचाएं

उपजाऊ शक्ति में वृद्धि | प्रदूषण से मुक्ति | अर्थव्यवस्था को गति

मिट्टी के रूप में मिले वरदान को नष्ट होने से बचाएं

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री — नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

ये विकल्प अपनाएं

हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम यंत्र का उपयोग

हैप्पी सीडर और सुपर सीडर का उपयोग कर सीधी बोनी

रीपर से कटाई के बाद जीरो टिलेज मशीन से सीधे बोनी

बेलर मशीन का उपयोग कर धान की पराली और मक्के के तने के बेल्स बनाएं

धान की पराली का प्लेट्स, ब्रिक्स और बायो फर्टिलाइजर के निर्माण में उपयोग

प्राकृतिक खेती को अपनाएं

मिट्टी की सतह पर सूक्ष्म जीवों के बढ़ावे से मिट्टी की उर्वर शक्ति में वृद्धि

रासायनिक पदार्थों से मुक्त होने से कैंसर जैसी घातक बीमारियों से मुक्ति

प्राकृतिक खेती से उत्पादन में कोई कमी नहीं

R.O. No. : D19257/25

आइये, स्वस्थ मिट्टी, स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन के लिए पराली न जलाने का प्रण लें....

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)